

गुलाम सरवर

बनाम

भारत संघ व अन्य

15 दिसंबर, 1966

[के. सुब्बा राव, सी. जे., एम. हिदायतुल्ला, एस. एम. सिकरी,

आर. एस. बचावत और जे. एम. शेलट, जे. जे.]

अभ्यास- उच्च न्यायालय द्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरण के जारी करने के लिए याचिका को खारिज करने का आदेश-उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के तहत याचिका प्रस्तुत की गई- क्या उच्च न्यायालय का आदेश प्रांग न्याय के सिद्धांत के तहत है ।

भारतीय संविधान, 1950, अनुच्छेद 359- यदि राष्ट्रपति एक से अधिक आदेश जारी कर सकते हैं- आदेश केवल विदेशी नागरिकों के लिए लागू होगा- यदि धारा 14 का उल्लंघन करता है।

विदेशी अधिनियम (1946 का 31), धारा 3(2)(जी)- सोना की तस्करी की साजिश के अनुसंधान के तहत हिरासत- यदि सद्भाविक है। सर्वोच्च न्यायालय की नियमावली, 0.35, नियम 3 और 4 का कार्यक्षेत्र ।

भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की धारा 352(1) के तहत आपातकाल की उद्घोषणा जारी की थी, उन्होंने धारा 359(1) के तहत दो आदेश जारी किए थे जिन्हें बाद में संशोधित किया गया था। एक आदेश द्वारा, संशोधित रूप में, आपातकाल के दौरान किसी भी विदेशी नागरिक को संविधान के धाराओं 14, 21 और 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में आवेदन करने के अधिकार को आपातकाल की अवधि के दौरान निलंबित किया गया था। दूसरे आदेश द्वारा, संशोधित रूप में, धारा 359(1) के तहत किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में आवेदन करने के अधिकार आपातकाल की अवधि के दौरान निलंबित किया गया था, यदि ऐसे व्यक्ति को भारतीय रक्षा अधिनियम, 1962, या उसके किसी नियम या आदेश के तहत किसी भी ऐसे अधिकार से वंचित किया गया था।

1964 में, यहां एक पाकिस्तानी नागरिक जिसे भारतीय कस्टम्स अधिनियम, 1962 के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था। जब उसे जमानत पर छोड़े ही जाने वाला था तो उसे 1946 के विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)(जी) के तहत आदेश द्वारा हिरासत में रखा गया था। उत्तरदाता के अनुसार, जांच की प्रक्रिया जारी थी एक सोने को तस्करी की साजिश के मामले में, जिसमें यहां याचिकाकर्ता शामिल था। इसके बाद, उसे कस्टम्स अधिनियम के तहत अपराध के लिए उसका ट्रायल किया गया और उसे 9 महीने की कैद सुनाई गई। कैद की अवधि की समाप्ति से

पहले उसने हेबियास कॉर्पस की एक याचिका के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। सजा पूरी करने के बाद उसने इस न्यायालय में पुनः धारा 32 के तहत हेबियास कॉर्पस की रिट याचिका नए तर्क के साथ प्रस्तुत की, जिसमें विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)(जी) और विदेशियों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश अंतर्गत धारा 359(1) की मान्यता के संबंध में आपत्तियों को उठाया गया था।

अभिनिर्धारित किया (सुब्बा राव, सी. जेड. हिदायतुल्लाह, सीकरी और शेलाट, जे): (1) उच्च न्यायालय का आदेश प्रांग न्याय होने की कार्यन्विति नहीं करता है, चाहे यह निर्णय न होने की वजह से हो या इस सिद्धांत के किसी मौलिक रूप से विधिविरुद्ध आदेश पर लागू नहीं होने की वजह से हो, और इस न्यायालय को मामले को गुणावगुण पर तय करना होगा । [277 D]

उच्च न्यायालय के मामले में, जब यह एक डिविजनल बेंच के रूप में कार्य करता है तो यह पूरे न्यायालय के लिए बोलता है, और इसलिए यह ताजा सबूतों को छोड़कर, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका में किसी अन्य डिविजनल बेंच द्वारा दिए गए आदेश को रद्द नहीं कर सकता है लेकिन जब व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक मूल याचिका दायर करता है। उच्च न्यायालय का आदेश पूर्व निर्णय के रूप में कार्य नहीं करेगा। यदि ऐसे मामले में पूर्व

निर्णय का सिद्धान्त लागू होता है, तो आन्वयिक पूर्व निर्णय का सिद्धांत भी लागू होगा, और, यदि कोई याचिकाकर्ता एक ऐसा विवाद उठा सकता है, जो हिरासत के आदेश को मौलिक रूप से कम कानून बना देगा, लेकिन उच्च न्यायालय में ऐसा नहीं किया गया। इसे उठाया गया माना जाएगा और यह न्यायालय यद्यपि संविधान द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने का आदेश दिया गया है। ऐसा करने से शक्तिहीन हो सकता है [276 एफ-एच: 277 ए-सी]

दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य(1) [1962] 1 एस.सी.आर. 574,
संदर्भित:

(2) अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को उल्लिखित उद्देश्य के लिए आदेश देने का अधिकार देता है और चूँकि एकवचन में बहुवचन भी सम्मिलित है। वह व्यक्तियों के विभिन्न समूहों पर अलग-अलग आदेश लागू कर सकता है। अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राष्ट्रपति को आदेश के दायरे को व्यक्तियों के एक वर्ग तक सीमित करने से रोकता है, जैसा कि विदेशी नागरिक। [280 ए-सी]

(3) राष्ट्रपति के आदेश और उस आदेश के प्रभाव में अंतर है। अनुच्छेद 359(1) के तहत राष्ट्रपति केवल वही आदेश दे सकता है जो वैध हो, यदि आदेश अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। यह अनुच्छेद 14 को लागू करने के लिए अदालत में जाने के अधिकार को वैध रूप से छीन

सकता है, लेकिन एक आदेश अनुच्छेद 14 के तहत अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने में अनुचित भेदभाव करता है। शुरु से ही शून्य हो जाएगा। इसलिए, राष्ट्रपति के आदेश की वैधता अनुच्छेद 359(1) के तहत जारी की गई है। क्या वह सवाल उठा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। [280 एफ-एच]

व्याख्या द्वारा: श्री मोहन चौधरी बनाम मुख्य आयोग, केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा (1964) 3 एस.सी.आर 442

(4) हालाँकि, विदेशियों और नागरिकों में वर्गीकरण और राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा प्राप्त की जाने वाले उद्देश्य के बीच एक स्पष्ट संबंध है। इसलिए लागू दो आदेश, एक विदेशियों तक सीमित और दूसरा विदेशियों सहित सभी व्यक्तियों पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। दोनों आदेश मुख्य रूप से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए हैं और उनका दायरा अलग-अलग है, हालांकि कुछ अतिव्यापी है। विदेशियों की विध्वंसक गतिविधियों से अधिक खतरा था इसलिए एक विशेष आदेश जारी करना आवश्यक था, जिसका दायरा व्यापक हो और अन्य अधिकारों को लिया जाए, जो केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित था जो भारत रक्षा अध्यादेश के तहत कुछ अधिकारों से वंचित थे। [282 ई.]

(5) राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अदालत जाने का अधिकार निलंबित कर दिया गया जो अनुच्छेद 14 अधिकारों को लागू करने के लिए

वैध है, याचिकाकर्ता को इसका कोई अधिकार नहीं है कि विदेशियों से संबंधित आदेशों में अनुच्छेद 14 को शामिल करने के लिए बाद में अदालत का रुख करें। खासतौर से कि उसने अपनी हिरासत की शिकायत की थी, संशोधन से पहले की अवधि के लिए संशोधन के प्रश्नों पर याचिका की पोषणीयता के विचार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। [282 एच; 283 ए)

(6) यदि याचिकाकर्ता वास्तव में सोने की तस्करी की साजिश में शामिल था, तो कोई कारण नहीं है कि केन्द्र सरकार को विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)(जी) के तहत उसे हिरासत में लेने की व्यापक शक्ति प्रदत्त की जाए। जांच के उद्देश्य से इस तरह हिरासत में रखना दुर्भावनापूर्ण नहीं था। [283 एफ-जी)

प्रश्न यह है कि क्या यह न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपातकाल घोषित करने या इसे जारी रखने में कार्यपालिका की कार्रवाई दुर्भावना से की गई है और यह उसकी शक्ति का दुरुपयोग है। इस प्रश्न पर न्यायालय द्वारा अपनी राय को खुल्ला रखा गया। (278 ई)

बच्चावत, जे: (1) उच्च न्यायालय द्वारा खारिज आदेश पूर्व न्याय के रूप में कार्य नहीं करता है और अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर रोक नहीं लगाता है। उन्हीं तथ्यों पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की मांग की जा रही है। याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में

जाने का मौलिक अधिकार है और इसलिए उसकी याचिका पर विचार किया जाना चाहिए और गुण-दोष के आधार पर उसकी जांच की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय का आदेश कोई निर्णय नहीं है; और उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी याचिका की पिछली अस्वीकृति केवल उन मामलों में से एक है जिन पर यह उच्चतम न्यायालय आदेश 35 नियम 3 व 4 के तहत विचार करने से इंकार कर सकता है। हालाँकि, याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 32 के तहत एक ही तथ्य पर एक से अधिक बार इस न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा। [283 एच; 284 ए-सी]

(2) यह मानते हुए कि अनुच्छेद 359(1) के तहत राष्ट्रपति का आदेश अनुच्छेद 13(2) के संदर्भ में विधि है और जिसे इस आधार पर अमान्य घोषित किया जा सकता है, कि यह अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त अधिकार को कम करता है या छीनता है। वर्तमान मामले में आदेश 14 भेदभावपूर्ण नहीं है और न ही इसका उल्लंघन हुआ है। [285 ई-एफ]

मूल. क्षेत्राधिकार रिट याचिका संख्या 1966, 155

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका।

आर. वी. पिल्लई, याचिकाकर्ता की ओर से

एन.एस. बिंद्रा और आर.एन. सुचथे, उत्तरदाता संख्या 1 से 3 के लिए।

सुब्बा राव, सी. जे., हिदायतुल्ला, सिकरी और शेलत, में जे. जे. सुब्बा राव, सी. जे. बच्चन, जे. ने एक अलग समवर्ती निर्णय दिया।

सुब्बा राव, सी. जे.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका याचिकाकर्ता की हिरासत की वैधता पर सवाल उठाती है। विदेशी अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम संख्या 31) के 3 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा)।

याचिकाकर्ता एक पाकिस्तानी नागरिक है जो बिना किसी यात्रा दस्तावेज के भारत में आया था। जिसे 8 मई, 1964 को भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। जिसे 9 मई, 1964 को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया और 18 मई, 1965 को उसे रिहा कर दिया गया। जब वह जेल से रिहा होने वाला था, तो केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3(2)(जी) के तहत उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया गया। ऐसा कहा गया कि उसे हिरासत में लेना पड़ा, क्योंकि सोने की तस्करी की साजिश के एक मामले के संबंध में पुलिस की जांच चल रही थी, जिसमें वह एक सदस्य था। 29 मई, 1965 को, उसे सीमा शुल्क अधिनियम के अपराध के लिए मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दिल्ली द्वारा दोषी ठहराया गया और 9 महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास और

2,000/- रुपये का जुर्माना अदा की सजा सुनाई गई। उस आदेश के विरुद्ध उनके द्वारा सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर की गई अपील खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता को कारावास की सजा हुई और जुर्माना भी अदा किया गया। कारावास की अवधि समाप्त होने से पहले, याचिकाकर्ता ने अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए दिल्ली में पंजाब उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट दायर की। विद्वान न्यायाधीश के समक्ष अधिनियम के 3(2)(जी) की संवैधानिक वैधता अनुवाद नहीं किया गया। उस याचिका को खन्ना, जे. ने गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया।

विद्वान न्यायाधीश ने माना कि धारा 3(2)(जी) ने सरकार को उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर हिरासत के उक्त आदेश देने के लिए अधिकृत किया है और न्यायालय किसी भी दुर्भावना के अभाव में इसकी वैधता पर सवाल नहीं उठा सकता है। उन्होंने अपने सामने उठाए गए इस तर्क को खारिज कर दिया कि साजिश के मामले में जांच पूरी करने के उद्देश्य से उस उप-धारा के तहत कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसमें ऐसी कोई सीमा नहीं पाई गई थी। संक्षेप में, उन्होंने योग्यता के आधार पर याचिका खारिज कर दी।

वर्तमान याचिका 12 मई, 1966 को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें उत्तरदाताओं के खिलाफ

बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए उन्हें इस आधार पर मुक्त करने का निर्देश दिया गया था कि अधिनियम के प्रावधान अमान्य थे।

इससे पहले कि हम याचिका के समर्थन में श्री आर. वी. पिल्लई द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों पर विचार करें, हम शुरुआत में उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एन. एस. बिंद्रा द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति से निपटेंगे। श्री एन.एस. बिंद्रा ने तर्क दिया कि खन्ना, जे. द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को खारिज करने का आदेश प्रभावी था। जैसा कि पूर्व निर्णय में किया गया है और वर्तमान आवेदन की ग्राह्यता पर रोक लगा दी गई है। उक्त विवाद के समर्थन में दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य(1) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया था। वहां, उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत गुण-दोष के आधार पर खारिज करते हुए मामले की सुनवाई के बाद यह कहा गया कि कोई भी मौलिक अधिकार सिद्ध नहीं हुआ न ही कोई उल्लंघन हुआ है और इसका उल्लंघन संवैधानिक रूप से उचित है। याचिकाकर्ता ने उस आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में अपील नहीं की; किन्तु उसने इस न्यायालय में समान तथ्यों पर और समान अनुतोष के लिए अनुच्छेद 32 के तहत एक स्वतंत्र याचिका दायर की।

इस न्यायालय ने माना कि इस न्यायालय में याचिका को पूर्व न्याय के सामान्य सिद्धांतों द्वारा बाधित किया जाएगा। वह निर्णय याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए अधिकार से संबंधित था। उस मामले में याचिकाकर्ताओं ने संपत्ति पर अपने मौलिक अधिकार को लागू करने की मांग की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन पर दिए गए आदेश में अस्वीकार कर दिया था। पूर्व निर्णय की दलील को कायम रखते हुए, इस न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संदर्भ में उक्त याचिका पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

"इंग्लैंड में, तकनीकी रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक याचिका पर पारित आदेश को एक निर्णय के रूप में नहीं माना जाता है और यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिकाओं को उनके द्वारा एक वर्ग में रखता है। इसलिए, हम नहीं सोचते हैं कि कई बंदी प्रत्यक्षीकरण आवेदनों की अंग्रेजी सादृश्यता वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं(1) [1962] 1 एस.सी.आर. 574, 590 जब वे अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं पर पुनर्न्यायिकता के आवेदन का विरोध करना चाहते हैं। हालांकि विषय से अलग होने से पहले हम इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि क्या बंदी

प्रत्यक्षीकरण के लिए बार-बार आवेदन करना हमारे संविधान के तहत सक्षम होगा। यह एक ऐसा मामला है जिससे वर्तमान कार्यवाही में हमारा कोई सरोकार नहीं है।"

एक निर्णय जो स्पष्ट रूप से एक प्रश्न को खुला छोड़ देता है वह स्पष्ट रूप से उक्त प्रश्न पर प्राधिकृत नहीं हो सकता है। 'उक्त प्रश्न, जो अब तक खुला छोड़ दिया गया था, अब निर्णय लिया जाना है।

इसके विपरीत, उस निर्णय की सत्यता वर्तमान याचिका में किसी भी पुनर्विचार की मांग नहीं करती है, क्योंकि यह अब हमारे सामने उठाए गए प्रश्न के दायरे से बाहर है।

यह हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के दायरे पर विचार करने की ओर ले जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की प्रकृति को कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, खंड 39 पेज नं. 424 में सही व संक्षेपित किया गया है।

इस प्रकार "बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका हिरासत में लेने वाले दूसरे व्यक्ति को निर्देशित एक रिट है, जो उसे, कैदी के शरीर को, एक निर्दिष्ट समय और स्थान पर प्रस्तुत करने का आदेश देता है, उसके कैद और हिरासत के दिन और कारण के साथ, पेश करने, प्रस्तुत करने और रिट देने वाले न्यायालय या न्यायाधीश इस संबंध में जो भी विचार करेगा।

ब्लैकस्टोन ने अपनी टिप्पणियों में उक्त रिट के बारे में इस प्रकार कहा है।

कि यह कानून की पूर्ववर्ती याचिका है, और इसकी जड़ें हमारे सामान्य कानून के स्तम्भ में गहराई से निहित हैं... यह संभवतः इंग्लैंड के संवैधानिक कानून के लिए ज्ञात सबसे महत्वपूर्ण रिट है, जो इस प्रकार है यह अवैध अवरोध या कारावास के सभी मामलों में त्वरित और अनिवार्य उपाय करता है। यह अति प्राचीन काल से है, इसके प्रयोग का उदाहरण एडवर्ड प्रथम के तैंतीसवें वर्ष में मिलता है।"

इस रिट को जॉन मार्शल, सी.जे. द्वारा "एक महान संवैधानिक विशेषाधिकार" के रूप में वर्णित किया गया है। एक प्रख्यात न्यायाधीश ने कहा, "इसे अप्रभावित बनाए रखने से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है"। इसे ब्रिटिश स्वतंत्रता के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया था। एक न्यायाधीश पर भारी जुर्माना लगाया जाता है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के आवेदन पर विचार करने से गलत तरीके से इनकार कर देता है। रिट का इतिहास सत्ता और स्वतंत्रता के बीच संघर्ष का इतिहास है। रिट अवैध प्रतिबंधों के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी उपाय प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। "बंदी प्रत्यक्षीकरण" का शाब्दिक अर्थ है "उसका शरीर रखना"। इस रिट के द्वारा

अदालत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के शव को उसके समक्ष लाने का निर्देश दे सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिरासत वैध है या अवैध। एंग्लोसैक्सन न्यायशास्त्र में रिट की यही प्रमुख स्थिति है।

हमें भारत में इस रिट के इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इसे संविधान के आर्टिकल 32 व 226 में शामिल कर लिया गया है।

पूर्व न्याय के सवाल पर, अंग्रेजी और अमेरिकी अदालतें इस बात पर सहमत थीं कि पूर्व न्याय का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर लागू नहीं होता है, लेकिन वे इस निष्कर्ष पर अलग-अलग आधारों पर पहुंचे। इंग्लैंड में यह माना गया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट में कोई निर्णय एक निर्णय नहीं था, और इसलिए यह न्यायिक के रूप में कार्य नहीं करेगा और उस आधार पर एक समय में यह सोचा गया था कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति विभिन्न न्यायाधीशों के समक्ष लगातार आवेदन दायर कर सकता है। लेकिन बाद में अंग्रेजी अदालतों ने माना कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति एक ही डिवीजन के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष या एक ही उच्च न्यायालय के विभिन्न डिवीजनों के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए लगातार याचिका दायर नहीं कर सकता है, इस आधार पर कि डिवीजनल कोर्ट पूरे डिवीजन के लिए बोलता है और वह संपूर्ण न्यायालय के लिए प्रत्येक डिवीजन, और एक डिवीजन उसी न्यायालय के दूसरे

डिवीजन के आदेश को रद्द नहीं कर सकता है [हेस्टिंग्स (1) (नंबर 2) और री हेस्टिंग्स (2) (नंबर 3) देखें]। न्याय प्रशासन अधिनियम, 1960 ने इस दृष्टिकोण को वैधानिक आधार पर रखा है, क्योंकि उक्त अधिनियम के तहत नए साक्ष्य के अलावा कोई भी दूसरा आवेदन उसी अदालत में नहीं लाया जा सकता है। अमेरिकी अदालतें भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचीं, लेकिन एक अलग सिद्धांत पर। एडवर्ड एम. फे बनाम चार्ल्स नोला (3) में निम्नलिखित परिच्छेद दिखाई देता है: "जैसा कि मिस्टर जस्टिस होम्स ने फ्रैंक बनाम मॅंगम (4) में कहा था: यदि याचिका उन तथ्यों का खुलासा करती है जो ट्रायल कोर्ट में अधिकार क्षेत्र के नुकसान के बराबर हैं, अधिकार क्षेत्र को कानून के किसी भी निर्णय द्वारा बहाल नहीं किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का ऐतिहासिक सार यह है कि इसमें कार्यवाहियों का परीक्षण करना मौलिक रूप से इतना अराजक है कि उनके अनुसार कारावास न केवल गलत है बल्कि शून्य है। इसलिए, न्यायिक सिद्धांत का परिचित सिद्धांत है बंदी कार्यवाही में अनुपयुक्त।" वही विचार वॉंग डू बनाम यूनाइटेड स्टेट्स (5) हार्मन मेट्ज वेली बनाम जेम्स ए. जॉन्सटन (6): सेलिंगर बनाम लोइसेल (7) यूनाइटेड स्टेट्स बनाम शौघनेसी (8): और अन्य में व्यक्त किया गया था।

लेकिन भारत के संदर्भ में, जहां तक उच्च न्यायालयों का प्रश्न है, अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा स्वीकार किया गया वही सिद्धांत समान रूप से लागू होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय खंडपीठों में नहीं, डिवीजनों में कार्य

करता है। जब यह एक डिवीजन के रूप में कार्य करता है, तो यह पूरे न्यायालय के लिए व्यक्त करता है, और इसलिए यह किसी अन्य डिवीजन बेंच द्वारा पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में दिए गए आदेश को रद्द नहीं कर सकता है। लेकिन यह सिद्धांत अलग-अलग अदालतों पर लागू नहीं होगा। इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास, नागपुर और पटना और पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालयों ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है, हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के क्रमिक आवेदन दायर किए जा सकते हैं।

लेकिन इंग्लैंड के विपरीत, भारत में हिरासत में लिया गया व्यक्ति स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय, अर्थात् इस न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष मूल याचिका दायर कर सकता है। उक्त रिट में उच्च न्यायालय का आदेश, ब्रिटिश और अमेरिकी न्यायालयों की तरह निर्णय नहीं है क्योंकि या तो यह एक निर्णय नहीं है या पूर्व न्याय का सिद्धांत मौलिक रूप से कानूनविहीन आदेश पर लागू नहीं होता है। यदि पूर्व न्याय का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए एक आवेदन की ओर आकर्षित होता है

- (1) (1958) 3 All.E.R. 625. (2) (1959) 1 All E.R. 698. (3) 9 L. Ed. 859. (4) 237 U.S. 348. (5) 68 L.E.D. 999. (6) 86 L. E.D. 132 (7)(1925) 265 U.S. 224 (8) (1954) 347 U.S. 260

तो कोई कारण नहीं है कि आन्वयिक पूर्व न्याय का सिद्धांत भी उक्त आवेदन को नियंत्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि आन्वयिक पूर्व न्याय, पूर्व न्याय के कानून का सामान्य सिद्धांत का केवल एक हिस्सा है और यदि इसे लागू किया जाता है, तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा काफी कम हो जाएगा। वर्तमान मामला स्थिति को दर्शाता है। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत दिए गए राष्ट्रपति के आदेश की संवैधानिक वैधता पर सवाल नहीं उठाया, यदि आन्वयिक पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू किया जाता है, हालांकि इसे संविधान द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने का आदेश दिया गया है, तो यह न्यायालय ऐसा करने में शक्तिहीन हो जाएगा। यह संवैधानिक संरक्षण के व्यापक दायरे को कम कर देगा।

इसलिए, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में दिया गया खन्ना, जे. का आदेश न्यायिक के रूप में काम नहीं करता है और इस न्यायालय को योग्यता के आधार पर याचिका पर फैसला करना होगा।

यह सुझाव दिया गया कि वर्ष 1962 में चीन के साथ शत्रुता समाप्त होने के बाद 4 वर्षों तक संविधान की अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर उसे जारी रखना दुर्भावनापूर्ण है जो संविधान के भाग XVIII

के तहत राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग है। उठाए गए प्रश्न में दो बिंदु शामिल हैं: (1) क्या आपातकाल की घोषणा या इसे जारी रखना दुर्भावना या शक्ति के दुरुपयोग से प्रेरित है, और (2) क्या ऐसा प्रश्न अदालत में न्यायसंगत है कि हमारा संविधान एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है जहां समृद्धि, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय हो। यह ऐसे राज्य को लाने के लिए तीन अवधारणाओं को स्वीकार करता है: (1) संघात्मक; (2) लोकतंत्र; (3) विधि का शासन, जिसमें मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय अभिन्न रूप से अंगीकृत हैं। भाग XVIII के तहत जब आपातकाल घोषित किया जाता है तो केन्द्र की विधायी और कार्यपालिका दोनों शक्तियां राज्यों तक बढ़ा दी जाती हैं। संघीय सरकार व्यावहारिक रूप से एकात्मक सरकार में तब्दील हो जाती है। लोगों के मौलिक अधिकार अर्न्तगत अनुच्छेद 19 को निरस्त कर दिया गया है और कार्यपालिका को किसी अन्य मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार दिया गया है। कार्यपालिका को यह निर्देश देने का भी अधिकार है कि उस अवधि के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित सभी या किसी अन्य प्रावधान को निलंबित कर दिया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि भाग XVIII हमारे संविधान की भव्य इमारत को एक झटके में ढहा देगा, लेकिन थोड़ा सा चिंतन करने से पता चलता है कि संविधान की योजना का अस्थायी निलंबन वास्तव में इसके सार को संरक्षित करने के लिए है। यह

असाधारण शक्ति हमारे संविधान के लिए अद्वितीय है। यह संविधान निर्माताओं की आकांक्षा और समय-समय पर सत्ता में आने वाली पार्टियों के प्रति उनके अंतर्निहित विश्वास को दर्शाता है। दो अभिव्यक्तियाँ उस असाधारण स्थिति को दर्शाती हैं जिसके तहत इस भाग को लागू करने का आशय था।

अनुच्छेद 352(1) में अभिव्यक्त 'गंभीर आपातकाल' और अनुच्छेद 352(3) में अभिव्यक्त 'आसन्न खतरा' यह दर्शाता है कि गंभीर आपातकाल या आसन्न खतरे का अस्तित्व आपातकाल की घोषणा के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। निःसंदेह, यह प्रश्न कि क्या गंभीर आपातकाल है या क्या आसन्न खतरा है, जैसा कि अनुच्छेद में उल्लिखित है, कार्यपालिका की संतुष्टि पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि वह स्थिति का आकलन स्पष्ट रूप से करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। लेकिन ऐसी असाधारण शक्ति के दुरुपयोग का खतरा अधिनायकवाद की ओर ले जाता है। निःसंदेह, आदर्श लोकतांत्रिक संविधान यानी जर्मनी के वाइमर संविधान की विकृतियों के कारण हिटलर का निरंकुश शासन और परिणामस्वरूप विनाशकारी विश्व युद्ध हुआ। ऐसे दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा क्या है? स्पष्ट सुरक्षा कार्यपालिका की अच्छी समझ है, लेकिन अधिक प्रभावी जनता की राय है। एक सवाल उठाया जाता है कि क्या यह न्यायालय यह पता लगा सकता है कि आपातकाल घोषित करने या इसे जारी रखने में कार्यपालिका की कार्यवाही दुर्भावना से प्रेरित है और उसकी शक्ति का दुरुपयोग है। हम इस प्रश्न पर

अपनी राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं क्योंकि उस संबंध में हमारे सामने कोई सामग्री नहीं रखी गई है। इसके लिए हमारे देश में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और आपातकाल जारी रखने के लिए सत्ता में बैठे व्यक्तियों के दिमाग में चल रहे उद्देश्यों पर सावधानीपूर्वक शोध की आवश्यकता है। चूंकि भौतिक तथ्य हमारे सामने नहीं रखे गए हैं, इसलिए हम इस मामले में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी राय व्यक्त नहीं करेंगे, जो इस समय लोगो को आंदोलित कर रहा है।

श्री पिल्लई ने तब तर्क दिया कि राष्ट्रपति की शक्ति के अनुच्छेद 359(1) में किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का वास्तविक संबंध होना चाहिए। भारत की सुरक्षा, और विवादित आदेश का ऐसा कोई संबंध नहीं था। राष्ट्रपति संविधान का आदेश अनुच्छेद 359(1) के तहत पढ़ता है:

"जीएसआर-1418/30-10-62: संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अधिकार-

(ए) एक विदेशी, या

(बी)

संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के लिए अनुच्छेद 352 के खंड (1) के तहत जारी आपातकाल की उद्घोषणा की अवधि के लिए निलंबित रहेगा, 26 अक्टूबर 1962 को लागू है।

संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इसके द्वारा आदेश संख्या जीएसआर-1418 दिनांक 30-10-1962 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं:

उक्त आदेशों में 'अनुच्छेद 21' शब्द और अंक के स्थान पर 'अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21' शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"

अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल तभी घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खतरा हो, चाहे वह युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से हो, या जब कोई आसन्न खतरा हो; और अनुच्छेद 359 के तहत जारी कोई भी आदेश भारत की सुरक्षा, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से कुछ संबंध अवश्य होगा। लेकिन आक्षेपित आदेश में तर्क बढे कि विवादित आदेश इतना व्यापक था कि एक विदेशी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित

कर दिया गया, हालांकि इस तरह के अभाव और भारत की सुरक्षा आदि के बीच कोई संबंध नहीं था। इसे अलग तरीके से कहने के लिए, तर्क यह था कि अनुच्छेद 359(1) के तहत आदेश का दायरा केवल उन कारणों के दायरे तक सीमित रखा जाना चाहिए जिनके आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। मौजूदा मामले में, यह कहा गया कि उक्त आदेश ने कार्यपालिका को सोने की तस्करी के संबंध में जांच का इंतजार करने के लिए याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने का अधिकार दिया। जिसका संभवतः भारत की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं हो सकता है। हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे सामने रखी गई सामग्री से हम संतुष्ट नहीं हैं कि याचिकाकर्ता की हिरासत का आपातकाल से कोई संबंध नहीं है।

अगला तर्क यह था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359(1) के तहत ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता जिसमें कि एक समान मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के संबंध में किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करता हो। इस तर्क की सराहना करने के लिए, यह उल्लेख किया जा सकता है कि विदेशियों से संबंधित 30-10-1962 के आदेश के अलावा, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं, राष्ट्रपति ने 3-11-1962 को एक आदेश पारित किया था जिसमें 11-11-1962 को संशोधन किया गया। संशोधित आदेश में घोषणा की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए

किसी भी व्यक्ति को किसी भी अदालत में जाने का अधिकार उस अवधि के लिए निलंबित रहेंगे, जिसके दौरान आपातकाल की उद्घोषणा जारी की गई थी। "यदि ऐसे व्यक्ति को भारत रक्षा अध्यादेश, 1962 (1962 का 4) या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के तहत ऐसे किसी भी अधिकार से वंचित किया गया है।" जो 26 अक्टूबर, 1962 के तहत अनुच्छेद 352 खंड (1) प्रभाव में आया।

यह देखा जाएगा कि दिनांक 30-10-1962 का आदेश विदेशियों तक ही सीमित था और दिनांक 3-11-1962 का आदेश उन व्यक्तियों तक ही सीमित था जो भारत रक्षा अध्यादेश, 1962 के तहत अपने अधिकारों से वंचित थे। अनुच्छेद 359 की शर्तों पर एक और विवाद उठाया गया कि उक्त अनुच्छेद 359 व्यक्तियों के विभिन्न समूहों पर आदेशों का पालन नहीं करता है। यह सच है कि अनुच्छेद 359 व्यक्तियों के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि केवल किसी भी अदालत में जाने के अधिकार की बात करता है और साथ ही एक अवधि, या एक हिस्से या पूरे क्षेत्र के बारे में भी बात करता है। लेकिन अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को उसमें उल्लिखित उद्देश्य के लिए आदेश देने का अधिकार देता है और चूंकि एकवचन में बहुवचन शामिल है, इसलिए वह निश्चित रूप से अलग-अलग आदेश दे सकता है। लेकिन सवाल यह है: क्या वह विदेशियों और भारत की रक्षा नियमों द्वारा शासित व्यक्तियों जैसे व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के संबंध में कोई आदेश या अन्य आदेश दे सकता है? यह सत्य है कि उसके आदेश

का दायरा भारत के संपूर्ण या उसके एक भाग तक तथा कुछ निश्चित अवधियों तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राष्ट्रपति को आदेश के दायरे को व्यक्तियों के एक वर्ग तक सीमित करने से रोकता है, बशर्ते कि आदेश का संचालन एक क्षेत्र और एक अवधि तक ही सीमित हो। विवादित आदेश पूरे देश पर लागू होते हैं और तथ्य यह है कि केवल वे व्यक्ति जो उस आदेश से प्रभावित होते हैं, वे अपने अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय का रुख नहीं कर सकते, उन्हें कम वैध आदेश नहीं दिया जा सकता है।

विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि अनुच्छेद 359(1) ने राष्ट्रपति को विदेशियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाला आदेश देने के लिए अधिकृत नहीं किया, और यदि ऐसा किया भी, तो तत्काल मामले में दिए गए आदेश ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं किया। क्योंकि विदेशियों और नागरिकों के वर्गीकरण और उस उद्देश्य के बीच कोई संबंध नहीं था जिसके लिए उक्त आदेश बनाया गया था।

विद्वान वकील श्री बिंद्रा ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत प्रदत्त सीमाओं के अधीन राष्ट्रपति को यह आदेश देने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है कि भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से एक या अधिक के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित रहना चाहिए और इसके तहत दिए गए किसी भी आदेश को इस आधार पर शून्य

घोषित नहीं किया जा सकता है कि इससे उक्त आदेश द्वारा निलंबित किए गए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इसलिए यह कहा गया था कि विपरीत दृष्टिकोण एक सर्कल में एक तर्क के समान होगा।

राष्ट्रपति द्वारा, एक संवैधानिक प्रावधान के तहत उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा एक संवैधानिक प्रावधान के बल पर मौलिक अधिकारों से वंचित करने के बीच स्पष्ट अंतर है। इस भेद को अनुच्छेद 358 के प्रावधानों की तुलना और अनुच्छेद 359 उचित ठहराता है। इसी अनुच्छेद 358 के बल पर ही अनुच्छेद 19 को पृथक रखा गया है। राष्ट्रपति को यह घोषणा करते हुए एक आदेश देना होगा कि भाग III में मौलिक अधिकार या अधिकारों के संबंध में अदालत में जाने का अधिकार निलंबित है, तब तक अनुच्छेद 359(1) अपने आप में प्रभावी नहीं है। वह केवल एक आदेश दे सकता है जो वैध हो। अनुच्छेद 14 के तहत अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने में अनुचित भेदभाव करने वाला आदेश स्वयं, इसकी शुरुआत में शून्य हो जाएगा। यह एक अभी भी जन्मजात आदेश है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें एक वृत्त में तर्क शामिल है। यह तर्क, उस क्रम के क्रम और प्रभाव के बीच के अंतर को अनदेखा करता है।

यदि आदेश अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है, यह अनुच्छेद 14 को लागू करने के लिए अदालत में जाने के अधिकार को वैधता प्रदान कर सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो, राष्ट्रपति अनुच्छेद

14 के आदेश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। श्री बिंद्रा ने अपने तर्क के समर्थन में श्री मोहन चौधरी बनाम मुख्य आयोग, केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा(1) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया कि राष्ट्रपति का आदेश अनुच्छेद 14 के प्रावधानों से अछूता था। जिस अनुच्छेद पर भरोसा किया गया है वह इस प्रकार है: "यह भी तर्क दिया गया था कि 3 नवंबर, 1962 का राष्ट्रपति का आदेश, इस शर्त के अधीन है कि एक वैध अध्यादेश है और उसके तहत बनाए गए नियम या दिए गए आदेश वैध हैं। दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता अध्यादेश की वैधता के बारे में प्रचार करने के लिए खुला है। यह एक दायरे में बहस कर रहा है। न्यायालय किसी विशेष अध्यादेश या विधायिका के अधिनियम की वैधता की जांच कर सके, इसके लिए न्यायालय का रुख करने वाले व्यक्ति के पास अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। यदि उसके पास न्यायालय का रुख करने का अधिकार नहीं है, तो न्यायालय विशेष कानून की वैधता पर सवाल उठाने वाली उसकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर देगा। संविधान के अनुच्छेद 359(1) के प्रावधानों के तहत पारित राष्ट्रपति के आदेश के अर्न्तगत, जैसा कि पहले ही बताया गया है, याचिकाकर्ता ने आपातकाल की अवधि के दौरान इस न्यायालय में जाने का अपना अधिकार खो दिया है। ऐसा होने पर, याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस अनुच्छेद का, अनुच्छेद 359(1) के तहत दिए गए आदेश की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है। इस न्यायालय ने जो कहा वह यह था कि,

अध्यादेश के तहत याचिकाकर्ता के पास कोई अधिकार नहीं था। अपने मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय का रुख करें, उसके पास अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि, वह अधिनियम की वैधता पर तभी सवाल उठा सकता था, जब वह इसके संबंध में न्यायालय का रुख कर सकता था।

(1) [1964] 3 एस. सी. आर, 442,451.

इसलिए, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 359(1) के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है अगर यह संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

अगला सवाल यह है कि क्या यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। श्री पिल्लई ने अपने तर्क दो तरह से रखे: (1) राष्ट्रपति ने अनुच्छेद के तहत दो आदेश दिये हैं। 359(1); (i) विदेशियों के संबंध में जीएसआर 1418 दिनांक 30-10-1962; और (ii) विदेशियों सहित सभी के संबंध में जीएसआर 164 दिनांक 3-11-1962 विदेशियों के संबंध में आदेश की शर्तें बिना किसी सीमा के हैं। लेकिन दिनांक 3-11-1962 का आदेश केवल उन व्यक्तियों को प्रभावित करता है जिन्हें भारत रक्षा अध्यादेश, 1962 या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के तहत आदेश में उल्लिखित किसी भी मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। ये दो आदेश अधिकारियों को अनुमति देते हैं। अपने विवेक से उस आदेश पर

भरोसा करने के लिए चिंतित हैं जो समान व्यक्तियों के संबंध में अधिक पूर्वाग्रहपूर्ण या कठोर है। (2) विदेशियों से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश भेदभावपूर्ण है क्योंकि इस तथ्य का कि कोई व्यक्ति विदेशी है, उसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, यानी राज्य की सुरक्षा, से कोई संबंध नहीं है।

वर्गीकरण के सिद्धांत का अंतर्निहित सूत्र इतना ठोस हो गया है कि निर्णयों का उल्लेख करना अनावश्यक है। सिद्धांत इस प्रकार कहा गया है: वर्गीकरण को सुगम अंतर पर पाया जाना चाहिए जो समूह से बाहर छोड़े गए लोगों से समूहीकृत व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है और यह कि अंतर का वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्न में कानून द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।" 30-10-1962 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश जीएसआर 1418 का उद्देश्य क्या था? भयंकर आपातकाल था. चीनियों ने भारत पर हमला कर दिया और पाकिस्तान हमले के लिए तैयार था। अंदरूनी तोड़फोड़ का खतरा था. इसलिए, विदेशियों की जांच करना और उनके तोड़फोड़ और जासूसी के कृत्यों से बचाव करना आवश्यक था। इसलिए, जीएसआर 164 दिनांक 3-11-1962 की तुलना में व्यापक दायरे में एक विशेष आदेश जारी करना आवश्यक था जो केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित था जो भारत रक्षा अध्यादेश के तहत कुछ अधिकारों से वंचित थे। विदेशियों से अधिक खतरा था, और इसलिए, एक अधिक कठोर आदेश ही राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था। विदेशियों की तुलना में, कुछ दुर्भाग्यशाली अपवादों को छोड़कर, देश की अखंडता और

सुरक्षा का समर्थन करने के लिए नागरिकों पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए, विदेशियों और नागरिकों के वर्गीकरण और इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच एक स्पष्ट संबंध है।

न ही हम इस तर्क की सराहना कर सकते हैं कि दो आदेश, एक विदेशियों तक सीमित और दूसरा विदेशियों सहित सभी व्यक्तियों तक सीमित, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। हालाँकि जीएसआर 164 नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी किसी विशेष अधिनियम के तहत वंचित उनके अधिकारों के संबंध में न्यायालय में जाने के अधिकार से वंचित कर सकता है, लेकिन उक्त आदेश (जीएसआर 164) का दायरा इससे बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है। विदेशियों की विध्वंसक गतिविधियाँ, यह केवल भारत रक्षा अध्यादेश के तहत वंचित अधिकारों तक ही सीमित है। जीएसआर 1418 में अधिक व्यापकता है और यह अन्य अधिकार लेता है। यद्यपि कुछ ओवरलैपिंग है, व्यक्तियों की दो श्रेणियां विदेशी और नागरिक-अलग-अलग सुरक्षा और अन्य समस्याएं पेश करती हैं। दोनों आदेश मुख्य रूप से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए हैं और उनका दायरा भी अलग-अलग है। इसलिए, हमें इस विवाद में भी कोई गुण नजर नहीं आता।

फिर यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति के आदेश जीएसआर 1276 दिनांक 27-8-1965 का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं है इस प्रकार,

याचिकाकर्ता अदालत का रुख करने का अधिकारी है। जीएसआर 1276 दिनांक 27-8-1965 को जारी किया गया था। उसमें अनुच्छेद 14 को शामिल करके पहले के आदेश में संशोधन किया गया था। इसलिए, 27-8-1965 के बाद, किसी भी विदेशी को अदालत में जाने का अधिकार नहीं है। हालांकि अनुच्छेद 14 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस संदर्भ में, आदेश भूतलक्षी नहीं बल्कि भविष्यलक्षी है। यह केवल किसी व्यक्ति के न्यायालय में जाने के अधिकार पर लागू होता है। चूंकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने 12 मई, 1966 को अपनी याचिका दायर की थी, यानी आदेश की घोषणा के बाद, उसके पास इसे स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। तथ्य यह है कि उन्होंने उस तारीख से पहले की अवधि के लिए अपनी हिरासत की शिकायत की थी, अदालत की याचिका के विचारणीयता के सवाल पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस विवाद में भी कोई दम नहीं है।

अंत में, यह तर्क दिया गया कि उसे हिरासत में लेने का आदेश दुर्भावना से प्रेरित था। दुर्भावना का तर्क इस प्रकार दिया गया: याचिकाकर्ता पर समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया जिसमें उसे 9 महीने की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। उसे आपराधिक मामला लंबित रहने तक गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने जुर्माना अदा किया और अपनी सजा काट ली। 18-3-1965 को उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल से निकलने से पहले ही

उसे विदेशी अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया। यह कहा गया था कि हिरासत राज्य की सुरक्षा से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं थी, बल्कि षडयंत्रकारियों का भारत में सोने की तस्करी की साजिश के एक मामले के संबंध में जांच करने के उद्देश्य से थी, जिसमें कथित तौर पर याचिकाकर्ता भी एक था। चूंकि उक्त जांच करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अन्य प्रभावी प्रावधान हैं, आगे तर्क दिया गया कि उक्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ता की हिरासत विदेशी अधिनियम के तहत शक्तियों का दुरुपयोग था। आगे यह तर्क दिया गया कि एस. विदेशी अधिनियम की धारा 3 का उद्देश्य भारत में और बाहर विदेशियों के प्रवेश और निकास को विनियमित करना था, इसका मामलों की जांच से कोई लेना-देना नहीं था, और इसलिए जांच के एकमात्र दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए उसे अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया था। 18 सितंबर, 1964 के हिरासत के आदेश में लिखा है: "विदेशी अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (जी) के सपठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार आदेश देती है कि पाकिस्तानी नागरिक श्री गुलाम मोहुद्दीन को गिरफ्तार किया जाएगा और अगले आदेश तक हिरासत में रखा जाएगा।" धारा(जी) केंद्र सरकार को किसी विदेशी को हिरासत में लेने का आदेश देने में सक्षम बनाता है। यह खंड उन कारणों का वर्णन नहीं करता है जिनके लिए उसे हिरासत में लिया जा सकता है। यदि, जैसा कि प्रत्यर्थी कहता है, याचिकाकर्ता सोने की

तस्करी की साजिश के एक गंभीर मामले में शामिल है और उस कारण से उसके आचरण के संबंध में आगे की जांच करने के लिए भारत में उसकी हिरासत आवश्यक थी, तो हम यह नहीं समझते हैं कि खंड (जी) के तहत उसे हिरासत में रखने के लिए केंद्र सरकार को दी गई व्यापक शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सका। इस तर्क में भी कोई दम नहीं है।

परिणामस्वरूप, याचिका खारिज की जाती है।

बच्चावत, जे. खन्ना, जे. के आदेश ने पंजाब उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पारित हिरासत आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी। विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(जी) के तहत और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक निर्णय नहीं है, और एक पूर्व न्याय के रूप में कार्य नहीं करता है। वह आदेश संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन पर रोक के रूप में बाधा कारित नहीं करता है। उन्हीं तथ्यों पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए कहता है। याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में जाने का मौलिक अधिकार है। इसलिए उसकी स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए वर्तमान याचिका पर विचार किया जाना चाहिए और गुण-दोष के आधार पर इसकी जांच की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के नियमों के आदेश 35, नियम 3 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए याचिका में बताया जाएगा कि क्या याचिकाकर्ता ने इसी तरह की राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का रुख किया है और यदि हां, तो क्या परिणाम होगा। यह नियम अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के मुद्दे के लिए एक याचिका के दुरुपयोग के खिलाफ एक हितकारी सुरक्षा उपाय है। उच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए याचिका की पिछली अस्वीकृति उन मामलों में से एक है जिसे यह न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई में विचार कर सकता है। क्या याचिका मंजूर करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, और यदि सभी सामग्रियों पर विचार करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो न्यायालय आदेश 35 नियम 4 के अंतर्गत रिट जारी करने से इनकार कर सकता है।

याचिकाकर्ता ने विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)(जी) के तहत हिरासत के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए पहले इस न्यायालय का रुख नहीं किया था। इसलिए, उसे रिट जारी करने के लिए इस न्यायालय में जाने का अधिकार है। लेकिन उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत एक ही तथ्य पर याचिकाकर्ता को गुण-दोष के आधार पर पूरी तरह से सुनने के बाद, अदालत उसे उन्हीं तथ्यों पर दोबारा नहीं सुनेगी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान याचिका किसी आपराधिक मुकदमे में पारित कारावास के आदेश की वैधता को चुनौती नहीं देती है। यह नहीं समझा जाना चाहिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपाय सक्षम आपराधिक न्यायालय के फैसले की औचित्य या वैधता का परीक्षण करने के लिए उपलब्ध है।

याचिकाकर्ता ने जीएसआर 1418 दिनांक 30 अक्टूबर, 1962 के तहत विदेशियों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश की वैधता को चुनौती दी। संविधान के अनुच्छेद 359(1) के आधार पर कि यह भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तर्क यह है: अनुच्छेद 359(1) अपने बल पर कार्य नहीं करता है। राष्ट्रपति को इसके तहत एक आदेश देना होता है जिसमें घोषणा की जाती है कि भाग III में मौलिक अधिकार के संबंध में न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित है। अनुच्छेद 13(2) के तहत राष्ट्रपति का आदेश अनुच्छेद 359(1) के अर्थ में एक विधि है। अनुच्छेद 359(1) के तहत एक आदेश जो मौलिक अधिकार को छीनता है या कम करता है, अनुच्छेद 13(2) के तहत शून्य है। इसलिए अनुच्छेद 359(1) के तहत एक आदेश की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है कि यदि यह अनुच्छेद 358 के तहत अधिकार के अलावा किसी मौलिक अधिकार को कम करता है या छीनता है, जो पहले से ही अनुच्छेद 19 के तहत निलंबित है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी का तर्क यह है - अनुच्छेद 359(1) के तहत राष्ट्रपति का एक आदेश भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए इस न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करना आवश्यक रूप से अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार को कम करता है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 359(1), अनुच्छेद 13(2) के अधीन एक कानून है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 359(1) के तहत कभी भी वैध आदेश नहीं दे सकता। यह रिडक्टियो एड एब्सर्डम है। यह मानना असंभव है कि राष्ट्रपति कभी भी अनुच्छेद 359(1) के तहत वैध आदेश नहीं दे सकते। निष्कर्ष यह होना चाहिए कि अनुच्छेद 359(1) के तहत राष्ट्रपति का आदेश अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में कोई कानून नहीं है। फिर से, राष्ट्रपति का एक आदेश अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर देता है। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त अधिकार को काफी हद तक कम करता है। यदि उपचार पूरी तरह से निलंबित कर दिया जाता है, तो अधिकार अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति का आदेश अनुच्छेद 359(1), अनुच्छेद 13(3)(ए) के अर्थ में एक कानून है, राष्ट्रपति कभी भी अनुच्छेद 359(1) के तहत कोई आदेश नहीं दे सकता, अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करना अनुच्छेद 14 के तहत एक असंभव निष्कर्ष है क्योंकि अनुच्छेद 359(1) की शर्तों के अनुसार राष्ट्रपति को अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त

अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने वाला आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है। एक आदेश जो अनुच्छेद 14 के व्यक्त शब्दों द्वारा 359(1) किसी अधिकार को कम कर सकता है या छीन सकता है, हालांकि अस्थायी रूप से इस आधार पर शून्य नहीं माना जा सकता है कि यह उस अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 359(1) का संदर्भ के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति का आदेश अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में कानून नहीं हो सकता।

मैं इस याचिका में यह निर्णय करने का प्रस्ताव नहीं रखता कि दोनों विरोधी तर्कों में से कौन सा स्वीकार किया जाना चाहिए। यहां तक कि इस मामले के प्रयोजन के लिए यह भी मान लिया जाए कि अनुच्छेद 359(1) के तहत राष्ट्रपति का आदेश अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में एक कानून है और इसे इस आधार पर अमान्य घोषित किया जा सकता है कि यह अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त अधिकार को कम करता है या छीनता है, विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारणों से मेरी राय है कि राष्ट्रपति का आदेश भेदभावपूर्ण नहीं है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।

मैं अन्य बिन्दुओं पर विद्वान मुख्य न्यायाधीश के निष्कर्ष एवं उनके द्वारा प्रस्तावित आदेश से सहमत हूँ।

वी. पी. एस.

याचिका खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक महावीर सिंह चारण (आर जे एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।